

Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
2.	IIT जोधपुर की भाषा संबंधी स्वदेशी AI तकनीक
3.	जनगणना - 2027 की राजस्थान में शुरुआत
4.	कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को ₹298 करोड़ का अनुदान
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. कवि डॉ. राजेश कुमार व्यास 2. डॉ. सुनयना प्रकाश : NCW की सलाहकार समिति में शामिल 3. श्री गंगानगर में दिखा 'फ़नल क्लाउड' 4. निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग के मध्य MoU
6.	स्पेसएक्स : 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण
7.	जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली
8.	उम्मीद पोर्टल (UMMEED)
9.	आयुर्वेद दिवस
10.	राष्ट्रीय खेल दिवस
11.	पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना
12.	प्रोजेक्ट आरोहण
13.	ग्लैंडर्स का उन्मूलन - राष्ट्रीय कार्य योजना

-- 1 --



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



14.	व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण
15.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24
16.	सिंकफील्ड कप, 2025
17.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. मोर, बरगद की जीनोम सिक्वेसिंग करने वाला



--: 2 ::--

राजस्थान परिदृश्य

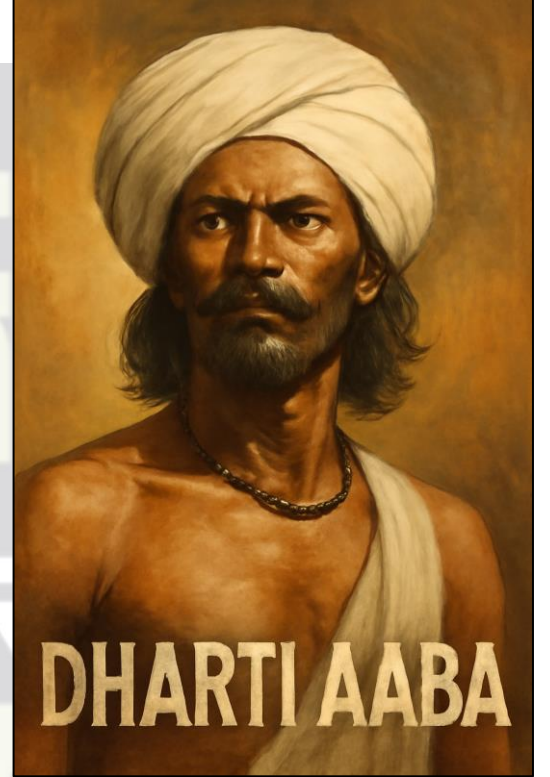
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

→ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राजस्थान के सभी 3 डिस्कॉम में रिवैम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RCDSS) के अंतर्गत 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' का क्रियान्वयन किए जाने की घोषणा की।

→ मुख्य बिन्दु :

- इसका उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी अंतराल को दूर कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- राजस्थान में इस योजना के तहत ऐसे गांवों को शामिल किया गया है, जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी निवासी हैं।
- साथ ही, इसमें आकांक्षी जिलों के वे गाँव भी सम्मिलित किए गए हैं, जहाँ आदिवासी जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे अधिक है।
- नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' के तहत राजस्थान के आकांक्षी जिले : बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही।



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

रिवैम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RCDSS)

- रिवैम्पड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम (RCDSS) भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक बिजली के नुकसान को कम करना, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना और उपभोक्ताओं के लिए बिजली सामर्थ्य सुनिश्चित करना है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA):

- कैबिनेट की स्वीकृति : 18 सितंबर, 2024
- शुरुआत : प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड के हज़ारीबाग़ से 2 अक्टूबर, 2024 (महात्मा गांधी जयंती)
- योजना का कुल परिव्यय : ₹79,156 करोड़ (केंद्र का हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्यों का हिस्सा : ₹22,823 करोड़)
- सम्बद्ध मंत्रालय : जनजातीय कार्य मंत्रालय।
- उद्देश्य : आकांक्षी जिलों में 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाओं की पहुँच स्थापित करना।
- यह अभियान 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गाँवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के लगभग 63,843 गाँवों को कवर करेगा और 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी लोगों को लाभान्वित करेगा।

IIT जोधपुर की भाषा संबंधी स्वदेशी AI तकनीक

→ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) जोधपुर के कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग विभाग ने 13 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट रीडिंग और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित करने की स्वदेशी AI तकनीक डवलप की है।



→ मुख्य बिन्दु :

- यह स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक संस्थान के विजन, लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप (VL2G) ने विकसित की है, जो 13 भारतीय भाषाओं में साइन बोर्ड, माइल स्टोन और अन्य टेक्स्ट का अर्थ समझाने में सक्षम है।
- यह तकनीक केंद्र सरकार की 'भाषिणी' परियोजना के तहत विकसित की गई है, इस तकनीक के माध्यम से 13 भाषाओं में टेक्स्ट को पढ़ने और अनुवाद करने के लिए इंडिक फोटो OCR डवलप किया है। इंडिक फोटो OCR एक ओपन-सोर्स मॉडल है, जो पूरी तरह स्वदेशी है।

- इससे पहले IIT जोधपुर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स (AIoT) पहल भी लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप, MSMEs और अंतिम उपयोगकर्ता उद्योग के लिए AIoT प्रणालियों के एंड-टू-एंड डिजाइन, विकास, प्रोटोटाइप और वितरण के लिए सुविधाएं विकसित करना है, जो इंडस्ट्री 4.0, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, पर्यावरण और जल प्रबंधन के अनुप्रयोगों में उपयोगी साबित होगा।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

भाषिणी प्लेटफॉर्म:

- भाषिणी भारत का AI-संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, जिसे 22 भारतीय भाषाओं में निर्बाध संचार और इंटरनेट पहुँच को सुगम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और डिजिटल समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए ध्वनि-आधारित तकनीक का उपयोग करता है।
- **विकास :** डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD) द्वारा।
- **मंत्रालय :** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

उद्देश्य :

- भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को सक्षम बनाना।
- बहुभाषी इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देकर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- भारतीय भाषाओं में नवाचार के लिए AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) संसाधनों हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

जनगणना - 2027 की राजस्थान में शुरुआत

➔ चर्चा में क्यों?

- राजस्थान के तीन जिलों क्रमशः जयपुर, बाड़मेर और डूंगरपुर में वर्ष 2025 के अंत में प्री-टेस्ट के साथ जनगणना-2027 की औपचारिक शुरुआत होगी।

➔ मुख्य बिन्दु :

प्री-टेस्ट के लिए चिह्नित क्षेत्र:

- जयपुर की एक कच्ची बस्ती।
- बाड़मेर शहर के 7 वार्ड।
- बाड़मेर जिले के दूरदराज के 21 गाँव।
- सांगवाड़ा (डूंगरपुर) आदिवासी क्षेत्र के 58 गाँव।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

जनगणना - 2027:

- भारत की 16वीं जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसकी संदर्भ तिथियाँ बर्फीले क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर, 2026 और देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 मार्च, 2027 होंगी।
- यह वर्ष 1931 के बाद पहली राष्ट्रव्यापी जाति-आधारित गणना होगी।

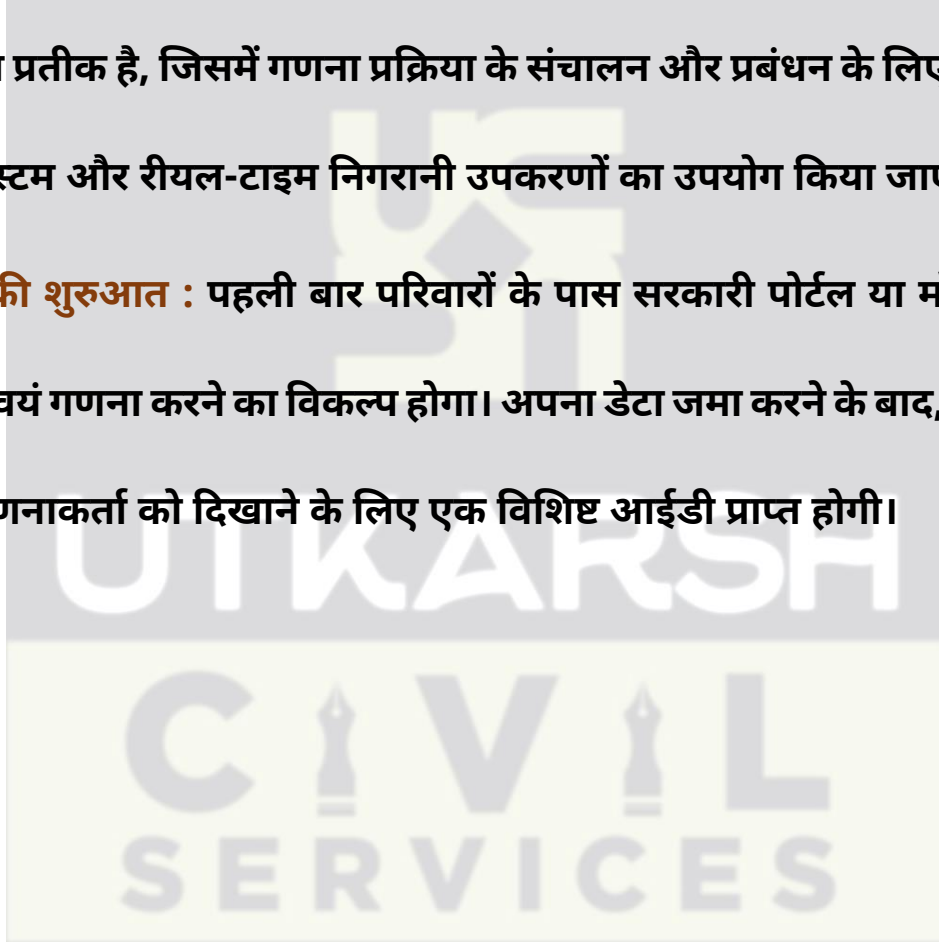


Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



- जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनगणना से पहले मकान-सूचीकरण और आवास सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है।
- **भारत में पहली डिजिटल जनगणना** : वर्ष 2027 की जनगणना भारत के डिजिटल ढाँचे में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें गणना प्रक्रिया के संचालन और प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप, क्लाउड सिस्टम और रीयल-टाइम निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- **स्व-गणना की शुरुआत** : पहली बार परिवारों के पास सरकारी पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं गणना करने का विकल्प होगा। अपना डेटा जमा करने के बाद, उन्हें सत्यापन के दौरान गणनाकर्ता को दिखाने के लिए एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होगी।



कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को ₹298 करोड़ का अनुदान

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 के तहत लम्बित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए ₹298 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।



➔ मुख्य बिन्दु :

- इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 855 कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों को पूंजी निवेश, ब्याज, सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत प्रभार अनुदान के साथ ही भाड़ा अनुदान दिया जाएगा।
- इस राशि का सम्पूर्ण भुगतान 'कृषक कल्याण कोष' से 'राज किसान पोर्टल' और आरपीपी के माध्यम से किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



- ज्ञातव्य है कि यह आवेदन 19 दिसम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रही राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019 के अन्तर्गत प्राप्त हुए है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक प्राप्त इन सभी लम्बित अनुदान आवेदनों के निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- कृषि प्रसंस्करण इकाई ऐसे बुनियादी ढाँचे है, जो सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के माध्यम से कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करता है।
- इनके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) संचालित की जा रही है।
- ये इकाइयाँ खेत से बाज़ार तक आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाएँ बनाकर किसानों की आय बढ़ाने, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>कवि डॉ. राजेश कुमार व्यास</p> <ul style="list-style-type: none">कवि डॉ. राजेश कुमार व्यास को 'कलाओं की अंतर्दृष्टि' रचना के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया गया।
2.	<p>डॉ. सुनयना प्रकाश : NCW की सलाहकार समिति में शामिल</p> <ul style="list-style-type: none">इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग की चेयरपर्सन एवं एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की वाइस चेयरपर्सन डॉ. सुनयना प्रकाश को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।डॉ. सुनयना प्रकाश को खेल जगत और विधिक क्षेत्र का व्यापक अनुभव हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की विधिक समिति की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं।

3.

श्री गंगानगर में दिखा 'फ़नल क्लाउड'

- ◆ हाल ही में, श्री गंगानगर के गाँव 23 आरबी संगराना में आसमान में एक प्राकृतिक घटना के रूप में 'फ़नल क्लाउड' देखा गया।
- ◆ फ़नल क्लाउड एक दृश्यमान, घूमता हुआ और संघनित वायु स्तंभ होता है जो गरज वाले बादल से निकलता है, लेकिन ज़मीन को नहीं छूता। यह बवंडर बनने का प्रबल संकेत होता है। फ़नल क्लाउड के ज़मीन से संपर्क होने पर सुपरसेल थंडरस्टॉर्म के रूप में विनाशकारी बवंडर बन सकता है।

4.

निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग के मध्य MoU

- ◆ हाल ही में, भारतीय निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- ◆ इसके तहत राजस्थान में कक्षा 9 से 12 में पढ़ रहे 17 वर्ष के विद्यार्थियों का पहले से मतदाता पंजीकरण कराना आसान होगा।
- ◆ यह व्यवस्था राज्य के सभी सरकारी और निजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्पेसएक्स : 10वां सफल स्टारशिप परीक्षण

→ चर्चा में क्यों?

- 26 अगस्त, 2025 को स्पेसएक्स ने टेक्सास के स्टारबेस से अपना दसवाँ स्टारशिप उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो दुनिया के पहले पूर्णतः पुनः प्रयोज्य रॉकेट के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



→ मुख्य बिन्दु :

- स्पेसएक्स ने पहली बार स्टारलिनक सिमुलेटर का उपयोग करके पेलोड तैनाती का प्रदर्शन किया।
- प्रक्षेपण वाहन : फाल्कन 9 रॉकेट।
- उद्देश्य : भविष्य के मिशनों हेतु महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करना, जिसमें वर्ष 2027 में नियोजित नासा का आर्टेमिस III चंद्रमा लैंडिंग भी शामिल है।

चरण :

- **सुपर हेवी बूस्टर (Super Heavy Booster) :** मैक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) में सफलतापूर्वक नियंत्रित स्प्लैशडाउन किया।
- **स्टारशिप अपर स्टेज (Starship Upper Stage) :** स्टारशिप के ऊपरी चरण ने अंतरिक्ष में सफल पुनः प्रज्वलन और हिंद महासागर में सॉफ्ट स्प्लैशडाउन सहित प्रमुख कार्य पूरे किए।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- **फाल्कन 9 रॉकेट :** स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा निर्मित विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट।
- **उपयोगी :** यह आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य (reusable) रॉकेट है जो पृथ्वी की कक्षा में पेलोड और मानव को ले जाता है।
- **दो चरण :** पहला चरण जो वापसी तथा दूसरा चरण जो पेलोड को कक्षा में पहुँचाता है।

राजव्यवस्था

जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली

➔ चर्चा में क्यों?

- 27 अगस्त, 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया।



➔ मुख्य बिन्दु :

- **सिफारिश :** कॉलेजियम (अध्यक्षता : मुख्य न्यायाधीश BR गवई)
- 1. कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 14 जजों के ट्रांसफर/मूल हाईकोर्ट में वापसी की सिफारिश की है।
- 2. दो न्यायाधीश को राजस्थान से दिल्ली हाईकोर्ट तथा एक न्यायाधीश को राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किया।

न्यायमूर्ति आलोक अराधे

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली

फरवरी, 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त।

वर्ष 2018 में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश।

जुलाई, 2023 में तेलंगाना और जनवरी, 2025 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त।

जून, 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

जुलाई, 2023 में पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ 21 जुलाई, 2025 को मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- **संवैधानिक प्रावधान :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं।

कॉलेजियम सिस्टम :

- **विकास :** प्रथम न्यायाधीश मामला (1981), दूसरा न्यायाधीश मामला (1993) तथा तीसरा न्यायाधीश मामला (1998) के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं।
- **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) :** एक संवैधानिक निकाय जिसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक (वर्ष 2015) करार दिया।

Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



न्यायाधीशों की अहताएँ :

	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
अनुच्छेद	124(3)	217(2)
प्रावधान	<ol style="list-style-type: none">1. भारत का नागरिक हो।2. किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो।3. किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।4. राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।	<ol style="list-style-type: none">1. भारत का नागरिक हो।2. भारत के राज्यक्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।



महत्त्वपूर्ण पोर्टल

उम्मीद पोर्टल (UMMEED)

➔ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथों को लाभ पहुँचाने के लिए उम्मीद पोर्टल पर नया मॉड्यूल लॉन्च किया।

GOVT LAUNCHES PORTAL FOR WAQF PROPERTIES



सत्यमेव जयते

➔ मुख्य बिन्दु :

- **उद्देश्य :** एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 के तहत कमजोर समूहों के लिए वित्तीय सहायता तक पहुँच में सुधार लाना।
- **प्रबंधन :** यह मॉड्यूल लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करता है और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन की अनुमति देता है।
- **भुगतान :** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा।

Daily Current Affairs

Date : 28 August, 2025



अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

उम्मीद पोर्टल :

- **लॉन्च :** 6 जून, 2025
- **पूर्ण रूप :** Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development (UMMEED)।
- **नोडल मंत्रालय :** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय।
- **उद्देश्य :** वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन एवं निगरानी को डिजिटल व पारदर्शी बनाना।
- **कानूनी ढाँचा :** यह पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम, 2025 के तहत कार्य करता है।
- **विशेषताएँ :** केंद्रीकृत डाटाबेस, पंजीकरण प्रक्रिया और अनिवार्यता तथा न्यायाधिकरण इत्यादि।

महत्त्वपूर्ण दिवस

आयुर्वेद दिवस

→ चर्चा में क्यों?

आयुर्वेद दिवस की घोषणा:

- भारत सरकार ने मार्च 2025 में एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से तय किया है कि आयुर्वेद दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा।
- पहले आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) को मनाया जाता था।



→ मुख्य बिन्दु :

2025 का विषय:

- आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय है: 'लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद'।
- इस वर्ष का विषय आयुर्वेद के समग्र स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान को दर्शाता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस

→ चर्चा में क्यों?

- इतिहास के महानतम फील्ड हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में भारत में प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

→ मुख्य बिन्दु :

- मेजर ध्यानचंद को 'हॉकी के जादूगर' के रूप में भी जाना जाता है।
- मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त, 1905 को प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था।
- उन्होंने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक हैट्रिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत सरकार ने वर्ष 2012 में हर साल उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी स्मृति में प्रति वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
- केंद्र सरकार द्वारा अगस्त, 2021 में 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' का नाम परिवर्तित करके 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' कर दिया गया।

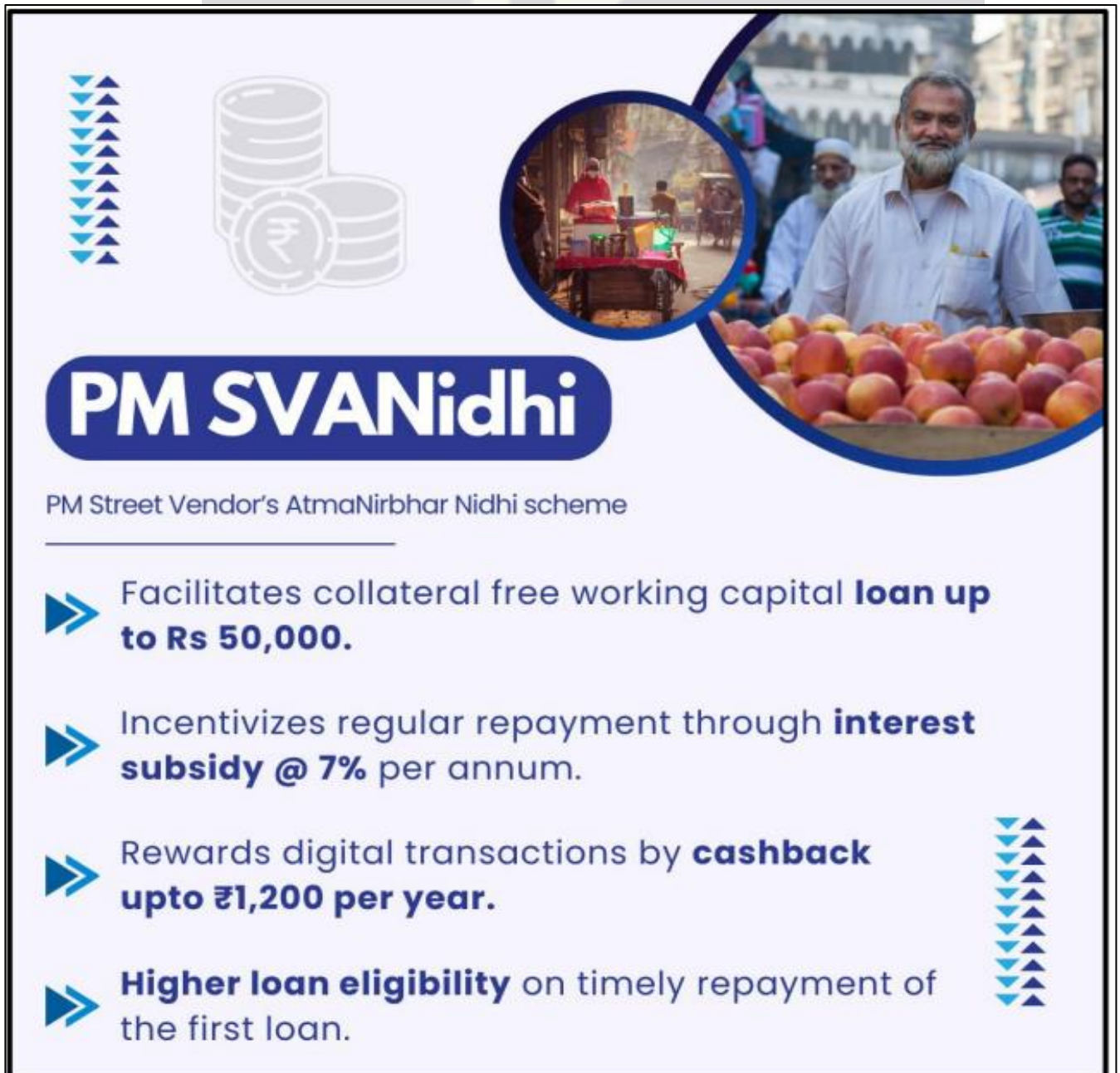


महत्त्वपूर्ण योजनाएँ

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना

➔ चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना' की अवधि को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया है।



PM SVANidhi

PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi scheme

- Facilitates collateral free working capital **loan up to Rs 50,000.**
- Incentivizes regular repayment through **interest subsidy @ 7% per annum.**
- Rewards digital transactions by **cashback upto ₹1,200 per year.**
- **Higher loan eligibility** on timely repayment of the first loan.

➔ मुख्य बिन्दु :

- योजना का कुल परिव्यय : ₹7,332 करोड़।
- पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है।
- योजना का कार्यान्वयन : आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा संयुक्त रूप से।
- वित्तीय सेवा विभाग (DFS) बैंकों या वित्तीय संस्थानों और उनके जमीनी स्तर के अधिकारियों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं।

योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण:

- प्रथम ऋण : ₹15,000 (पूर्व में ₹10,000)
- द्वितीय ऋण : ₹25,000 (पूर्व में ₹20,000)
- तृतीय ऋण : ₹50,000 (अपरिवर्तित)

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अभूतपूर्व कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए 1 जून, 2020 को एक नई योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) की शुरुआत की गई।
- इस योजना के तहत 30 जुलाई, 2025 तक 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी-पटरी वालों को ₹13,797 करोड़ के 96 लाख से ज़्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं।
- योजना की सफलता : वित्तीय समावेशन, आजीविका, अर्थव्यवस्था और डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार - 2023' से सम्मानित किया जा चुका है।

प्रोजेक्ट आरोहण

→ चर्चा में क्यों?

- एनएचएआई ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ मिलकर 'प्रोजेक्ट आरोहण' की शुरुआत की है।



→ मुख्य बिन्दु :

- यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करती है।

- परियोजना का शुभारंभ: 7 अगस्त 2025 को परियोजना की शुरुआत की गई।

- पहला चरण: 1 करोड़ रुपये का आवंटन, जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक चलेगा।

सहयोगी संस्थाएँ:

- एनएचएआई और वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा यह परियोजना संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को आर्थिक और शैक्षिक समर्थन देना है।

ग्लैंडर्स का उन्मूलन - राष्ट्रीय कार्य योजना

➔ चर्चा में क्यों?

- पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (डीएचडी) ने ग्लैंडर्स रोग पर संशोधित राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की है।
- योजना का उद्देश्य पूरे देश में ग्लैंडर्स की निगरानी, रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन को बढ़ावा देना है।

➔ मुख्य बिन्दु :

ग्लैंडर्स रोग:

- ग्लैंडर्स एक संक्रामक और घातक रोग है, जो मुख्य रूप से घोड़ों, खच्चरों और गधों जैसे अश्वों को प्रभावित करता है।
- यह रोग बर्कहोल्डरिया मैलेई नामक जीवाणु के कारण होता है, और यह अन्य पशुओं और मनुष्यों के लिए भी खतरनाक हो सकता है।
- यह रोग पशुओं में संक्रामक और संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण (पीसीआईसीडीए) अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अधिसूचित है।

लक्ष्य:

- इस कार्य योजना का उद्देश्य ग्लैंडर्स रोग के प्रसार को रोकना और इसके प्रभाव को कम करना है।
- पूरे देश में रोग की पहचान, परीक्षण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को मजबूत करना।

आर्थिक परिदृश्य

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 80 वें दौर में सीएमएस एजुकेशन सर्वेक्षण, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में वर्तमान में नामांकित छात्रों के घरेलू खर्च पर केंद्रित था।

मुख्य बिन्दु :

सरकारी स्कूलों में दाखिला:

- देश के कुल छात्रों का 55.9% हिस्सा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या शहरी क्षेत्रों (30.1%) की तुलना में अधिक है, जहां 66.0% छात्र पढ़ाई करते हैं।
- सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र औसत व्यय 2,863 रुपये था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह 25,002 रुपये था।

पारिवारिक वित्तपोषण:

- 95% छात्रों के वित्तपोषण का स्रोत परिवार के सदस्य थे। सरकारी छात्रवृत्तियाँ सिर्फ 1.2% छात्रों के लिए प्रमुख स्रोत थीं।

सामाजिक व आर्थिक प्रभाव:

- पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी पर शिक्षा का प्रमुख खर्च हुआ।
- शहरी क्षेत्रों में खर्च अधिक था, खासकर उच्च शिक्षा के स्तर पर।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- यह सर्वेक्षण सरकारी और निजी शिक्षा के खर्चों, कोचिंग की आदतों, और शिक्षा के लिए परिवारों द्वारा किए गए खर्चों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एसआई) 2023-24

→ चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एसआई 2023-24 के परिणामों को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने जारी किया।
- यह सर्वेक्षण उत्पादन, मूल्यवर्धन, रोज़गार, पूंजी निर्माण जैसे मानदंडों पर जानकारी प्रदान करता है।



→ मुख्य बिन्दु :

सकल मूल्य वर्धन (GVA) में वृद्धि:

- 2023-24 में सकल मूल्य वर्धन (GVA) में पिछले वर्ष की तुलना में 11.89% की वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि:

- औद्योगिक उत्पादन 2023-24 में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.80% बढ़ा।

रोजगार में वृद्धि:

- इस क्षेत्र में रोजगार में 2023-24 में 5.92% की वृद्धि हुई।
- पिछले एक दशक (2014-15 से 2023-24) में उद्योग ने 57 लाख से अधिक नौकरियाँ जोड़ीं।

Key Highlights of ASI 2023-24

ASI 2023-24 Central Sample Size - 83,620 (63,981 Census and 19,639 Sample)

Growth in current prices in the year 2023-24 over 2022-23



Main drivers of this growth in 2023-24 were in industries, Manufacture of Basic metal, Motor vehicles, Chemical and Chemical products, Food Products and Pharmaceutical products, leading to..

48% Contribution in total output of the sector.

6.35% Output Growth

12.29% GVA growth

The sector added more than 57 lakh jobs during the last decade 2014-15 to 2023-24.



Employment showed a robust Year-on-Year (Y-o-Y) growth of 5.92% in comparison to 2022-23

Compared to 2022-23, Average emoluments per persons engaged grew by

5.6%



मुख्य उद्योग:

- जीवीए के संदर्भ में शीर्ष 5 उद्योग: मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, दवा उत्पाद।

रोजगार के मामले में शीर्ष राज्य:

- रोजगार के मामले में शीर्ष 5 राज्य: तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 में सकल मूल्य वर्धन, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिली है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उद्योगों के विकास और संरचना में परिवर्तन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।

खेल परिदृश्य

सिंकफील्ड कप, 2025

→ चर्चा में क्यों?

- भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानंद ने सिंकफील्ड कप में उपविजेता बनकर ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल में क्वालीफाई किया।



→ मुख्य बिन्दु :


- आयोजन : 14 से 29 अगस्त, 2025
- विजेता : वेस्ली सो (अमेरिकी)।
- उपविजेता : आर. प्रज्ञानंद (भारत)।
- प्रज्ञानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लेवोन अरोनियन के साथ ड्रॉ खेला और कारूआना को टाई ब्रेक में हराकर एक अंक से दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कारूआना को टाई ब्रेकर के बाद तीसरे स्थान पर रहे ।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

सिंकफील्ड कप :

- आयोजक : सेंट लुइस शतरंज क्लब द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता हैं।
- कुल पुरस्कार राशि : 350,000 डॉलर।

न्यूज़ इन शॉर्ट्स

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>ऑपरेशन 'रेनबो'</p>  <p>Operation Rainbow</p> <p>♦ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन 'रेनबो' के तहत बड़ी कार्रवाई की।</p>

CIVIL
SERVICES